हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

2 RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

वर्ष:4 अंक:245 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, मंगलवार, 09 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन में गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां

पथ प्रवाह, संवाददाता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रतिभाग कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ÷रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म÷ की नीति के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उत्तराखंड भी विकास व समृद्धि की नई ऊँचाइयों को छू रहा है।

कार्यक्रम में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, उद्यमी, व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी व जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रबुद्धजन प्रधानमंत्री के ÷विकसित भारत ञ्2047÷ संकल्प को साकार करने वाले अग्रदूत हैं।

आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। आज गांव-गांव तक डिजिटल लेन-देन की सुविधा पहुंच चुकी है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

उत्तराखंड में निवेश का नया दौर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, 30 से अधिक नीतियां और मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 1 लाख करोड़ रुपये को धरातल पर उतारा जा चुका है। काशीपुर, सितारगंज और पंतनगर में नए इंडस्ट्रियल पार्क और क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि 'एक जनपद दो उत्पाद', 'हाउस ऑफ हिमालयाज', 'स्टेट मिलेट मिशन', 'नई पर्यटन व फिल्म नीति' और 'वेड इन उत्तराखंड' जैसी योजनाओं से स्थानीय उत्पादों और आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा है।

ऐतिहासिक फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। साथ ही प्रभावी नकल विरोधी कानून से पिछले साढ़े तीन साल में 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने लैंड जिहाद व अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नौ हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई है।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्वदेशी अपनाने का आह्वान

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ मंत्र को आत्मसात करें।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, शिव अरोड़ा, महापौर दीपक बाली सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

नेपाल में बवाल: कोर्ट के आदेश की अनदेखी और सरकार की सख्ती...

सोशल मीडिया पर बैन-भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा संसद में घुसे, सेना की फायरिंग,नेपाल में 20 मौतों, 250 घायल

काठमांडू। नेपाल में सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू कर दिया गया। इस प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हुई, जबकि 250 से ज्यादा घायल हो गए। इस प्रदर्शन की अगुआई जेन-जेड यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने की। इस दौरान सेना की फायरिंग में 18 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से अधिक घायल हुए हैं।

सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार सुबह 12 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी युवा संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोडफ़ोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं।

सरकार के मनमाने फैसलों से बढ़ा गुस्सा

नेपाल के पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल ने कहा कि सरकार के मनमाने और गलत फैसले और सुशासन देने में नाकामी के चलते युवाओं का गुस्सा बढ़ गया है। बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले और सरकारी नियुक्तियों की खरीद-फरोख्त सुनते-समझते आ रहे युवा पीढ़ी में गुस्सा बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार पर दमन के आरोप लगाए हैं। एक प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण

विरोध करना चाहते थे, लेकिन आगे बढने पर देखा कि पुलिस हमला कर रही थी और लोगों पर गोली चला रही थी। सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत हम पर नहीं थोप सकते। भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन दबाए जा रहे हैं, जो बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है।

नेपाल में सोशल मीडिया फिर से शुरू

नेपाल में सोशल मीडिया फिर से शुरू हो गया है। भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक, नेपाल में दोपहर 3ः15 बजे के बाद बिना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल किए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से सात दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई।

नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

यह कदम नेपाल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि घरेलू और विदेशी सभी ऑनलाइन और सोशल प्लेटफॉर्म्स का आधिकारिक पंजीकरण जरूरी है ताकि अनचाहे कंटेंट पर निगरानी रखी जा सके।

मंत्रालय ने कंपनियों को 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया था। इन हालातों ने नेपाल की सडक़ों पर गुस्से का माहौल खड़ा कर दिया है और भारत ने सावधानी बरतते हुए अपनी सीमा सुरक्षा और चौकसी को और मज़बूत कर दिया है।

नियमों के मुताबिक हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना, गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कानूनी नोटिसों का जवाब देना जरूरी कर दिया गया है।

इसके साथ ही सरकार के साथ यूजर डेटा शेयर करने के नियम भी मानना जरुरी कर दिया गया। कंपनियों को डेटा-प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में ये शर्तें बहुत सख्त लग रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत या यूरोप जैसे बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि रख लेती हैं, क्योंकि वहां यूजर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन नेपाल का यूजर बेस छोटा है, इसलिए कंपनियों को यह बेहद खर्चीला लगा। अगर कंपनियां नेपाली सरकार की यह शर्त मान लेती हैं, तो उन पर अन्य छोटे देशों में भी इन नियमों को पालन करने का दबाव पड़ता, जो काफी खर्चीला है। यही वजह रही कि पश्चिमी कंपनियों ने नेपाल सरकार की शर्त नहीं मानी और तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

नेपाल में बवाल के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा टाइट

नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार स्स्क्च (सशस्त्र सीमा बल) ने सीमा पर अतिरिक्त ट्रूप्स और सर्विलांस तैनात किए हैं। भारत-नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा स्स्क्च के जिम्मे है और हालात को देखते हुए निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है। नेपाल में हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

एक नजर

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से ले अधिकारी : जिलाधिकारी

पथ प्रवाह हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एल 1 पर 81 तथा एल 2 पर 22 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके स्तर पर जो भी शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित है उसका निस्तारण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करे, इसमें किसी भी प्रकार से कोई स्थिलता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को सभी अधिकारी गंभीरता से ले। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, एडीएम वित्त दीपेंद्र सिंह नेगी, सीएमओ आरके सिंह, परियोजना निर्देशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह, अधीक्षण अभियंता जल निगम एम मुस्तफा, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, डीएसओ तेजबल सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत आदि मौजूद रहे।

हरिद्वार नगर निगम अवैध तारों के जाल के जंजाल से दिला रहा मुक्ति

पथ प्रवाह, हरिद्वार। शहर की सुरक्षा और सौंदर्य बनाए रखने के लिए हरिद्वार नगर निगम ने सोमवार को अवैध तारों के जंजाल के खिलाफ अभियान चलाया। निगम की टीम ने रेलवे स्टेशन से सहगल पेट्रोल पंप तक नगर निगम के स्ट्रीट लाइट पोलों पर लगे डिश टीवी और इंटरनेट फाइबर के तारों को हटाया।

नगर निगम द्वारा इससे पहले भी 04 सितंबर 2025 को शिवमूर्ति चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक अवैध रूप से लगे तारों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को भी अभियान चलाया गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। आने वाले दिनों में मध्य हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल, खड़खड़ी, भीमगोड़ा और घाट क्षेत्रों में भी अवैध तार हटाए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने समस्त नागरिकों और सेवा प्रदाता कंपनियों से अपील की है कि बिना अनुमति स्ट्रीट लाइट पोलों या सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तार, केबल अथवा उपकरण न लगाएं। जिन स्थानों पर तारों का अवैध और अनियंत्रित जंजाल है, उन्हें तत्काल हटा लिया जाए।

सीएस की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद के मध्य सामंजस्य बैठक

मुख्य सचिव ने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे बाईपास के लिए राजाजी नेशनल पार्क, रेलवे और डीएफओ की टीम को शीघ्र से शीघ्र संयुक्त सर्वेक्षण कराये जाने के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में प्रदेश सरकार और डीआरएम मुरादाबाद संग्रह मौर्य के मध्य सामंजस्य बैठक हुई। बैठक के दौरान रेलवे और राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुयी। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे बाईपास के लिए राजाजी नेशनल पार्क, रेलवे और डीएफओ की टीम को शीघ्र से शीघ्र संयुक्त सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर ली जाए। उन्होंने हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य में तेजी लाए जाने हेतु रेलवे, वन एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि महाकुम्भ 2033 से पहले हरिद्वार-देहरादून डबल लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस और फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे से कुंभ मेला के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्कुलेशन प्लान भी शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने रेलवे स्टेशंस का फेस लिफ्टिंग

में ऋषिकेश एवं हरिद्वार को भी शामिल किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने रेलवे से कुम्भ 2027 से सम्बन्धित बैठकों में कॉर्डिनेशन के लिए एक मेला अधिकारी नामित किए जाने की बात कही। कहा कि कुम्भ की तैयारियों को लेकर होने वाली आगामी बैठक में रेलवे से भी प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने रेलवे और उत्तराखण्ड सरकार के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी मैकेनिज्म तैयार किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य के लिए मोबिलिटी प्लान तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के यातायात साधनों और विकल्पों को लेकर अगले 50 सालों का प्लान तैयार किए जाने की बात कही। डीआरएम श्री संग्रह मौर्य ने बताया कि देहरादून मसूरी रेलवे प्रोजेक्ट का प्राथमिक सर्वे हो गया है, फाइनल लोकेशन सर्वे शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहारनपुर देहरादून प्रोजेक्ट का फाइनल लोकेशन सर्वे गतिमान है। उन्होंने बताया हर्रावाला रेलवे स्टेशन की डीपीआर स्वीकृत हो गई है। प्रोजेक्ट की स्वीकृति होनी बाकी है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव बृजेश कुमार संत, सी रविशंकर, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा, उपाध्यक्ष एमडीडीए एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

GST दरों में सुधार से युवाओं को बनाएंगे सशक्त, फिटनेस को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल ही में किए गए सुधार देश के युवाओं को सशक्त बनाने, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और समग्र जीवन-यापन को सुगम बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम हैं। जीएसटी दरों में किए यह सुधार फिट इंडिया मूवमेंट जैसी राष्ट्रीय पहलों और युवा-केंद्रित गतिशीलता एवं बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के चल रहे प्रयासों के साथ जुड़े होने के कारण युवाओं और खेल क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सुधार खेल और फिटनेस गतिविधियों

में बढ़ती भागीदारी और देश भर के युवाओं के लिए अवसरों तक व्यापक पहुंच को बढ़ावा देंगे।

सभी के लिए फिटनेस

जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से नागरिकों, खासकर शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फिटनेस सुविधाएं और अधिक सुलभ हो जाएंगी। इस कदम से फिटनेस गतिविधियों और निवारक स्वास्थ्य सेवा में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो सीधे तौर पर फिट इंडिया अभियान के उद्देश्यों को बल प्रदान करेगा। यह जीएसटी सुधार लागत कम करके अधिक लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पूरे देश में फिटनेस की एक मज़बूत संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम बनाएगा।

किफायती दाम पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन

साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से नागरिकों के लिए पर्यावरण-अनुकूल परिवहन अधिक सुलभ और किफ़ायती हो जाएगा।

यातायात पुलिस ने दी गोल्डन आवर की महत्वपूर्ण जानकारी

पथ प्रवाह हरिद्वार। हरिद्वार जनपद की यातायात पुलिस वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। इसके लिए यातायात पुलिस स्कूल, कॉलेजों और कंपनियों में जाकर वहां के स्टॉफ को जागरूक कर रही है। अभियान के तहत गुड समैरिटन, ट्रैफिक साइन, सिग्नल, गोल्डन आवर आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी यातायात पुलिस दे रही है।

इसी क्रम में सोमवार को यातायात निदेशालय उत्तराखंड के आदेश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में तथा पुलिस उपाधीक्षक यातायात के नेतृत्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में यातायात व सीपीयू पुलिस रुड़की द्वारा यातायात संबंधी जानकारी दी गई। पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण व वीडियो विजुअल एड के माध्यम से इंडियन ऑयल टैंकर चालकों, सिक्योरिटी गार्ड सहित स्टॉफ कर्मचारी गणों को यातायात नियमों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए गुड समैरिटन, ट्रैफिक साइन, सिग्नल, गोल्डन आवर आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

सभी चालकों, स्टाफ व कर्मचारी गणों के साथ अखिलेश मंडल डीजीएम टर्मिनल व भीम सिंह नेगी मैनेजर टर्मिनल आईओसीएल द्वारा यातायात संबंधी जानकारी को महत्वपूर्ण बताते हुए यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया गया तथा पुलिस व सीपीयू रुड़की टीम का आभार व्यक्त किया गया। प्रशिक्षण यातायात निरीक्षक संदीप सिंह नेगी, यातायात उपनिरीक्षक सीपीयू हरीश अधिकारी व यातायात व सीपीयू टीम रुड़की द्वारा प्रदान किया गया।

जनसुनवाई में आयी 81 शिकायतें, 30 का जिलाधिकारी ने मौके पर किया निस्तारण

पथ प्रवाह हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जनसुवाई के दौरान जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 81 शिकायतें आयी जिनमें से जिलाधिकारी ने 30 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कराया। जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सोमवार को जनसुनवाई के तहत ग्राम प्रधान बिस्मिल्ला ने ग्राम गैंडीखाता में जंगल के पानी को रोकने के लिए तटबंध के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र दिया। ग्राम गैंडीखाता में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बैठक के लिए भवन निर्माण और गैंडीखाता पोस्ट ऑफिस को जनपद बिजनौर यूपी से हटाकर हरिद्वार में संचालित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। जगदीश

प्रसाद पुत्र नाथु सिंह निवासी ग्राम हरजोली जट ने अपनी भूमि खसरा नंबर 757 स्थित मौजा हरजोली जट की पैमाईश वास्ते प्रार्थना पत्र दिया। तबस्सुम निवासी मुकर्रमपुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयनित अभ्यार्थी के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत ही नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। प्रार्थी प्रमोद कुमार ने जिला समाज कल्याण हरिद्वार के द्वारा पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर बैंक को दी जाने वाली एनओसी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। रीता पत्नी मनोज निवासी ग्राम रहमतपुर ब्लॉक रुड़की ने आवासीय पक्का मकान स्वीकृत किए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया, कमल सिंह बिष्ट ने लालढांग में उसकी भूमि पर सिंचाई के लिए बनी गुल पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है, उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं स्थिलता नहीं होनी चाहिए, स्थिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।

हरिद्वार मेयर किरण जैसल और आयुक्त नंदन कुमार ने जलभराव से जनता को दिलाई राहत

संदेशनगर, कनखल क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए उपनगर आयुक्त श्री दीपक गोस्वामी

नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार

मेयर किरण जैसल

पथ प्रवाह, हरिद्वार

भारी बरसात के दौरान हरिद्वार नगर निगम ने अपने बेहतरीन प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई से शहरवासियों को बड़ी राहत दी। आयुक्त नंदन कुमार के निर्देशों पर निगम प्रशासन की टीम लगातार फील्ड में डटी रही और सुनियोजित तरीके से काम करते हुए जलभराव की समस्या पर नियंत्रण बनाया। मेयर किरण जैसल भी मोर्चा संभाले रही और जलभराव वाले इलाकों में पहुंचकर नगर निगम कर्मचारियों को निर्देशित करती रही।

मानसूनी सीजन में आसमान से हुई जबरदस्त बारिश ने हरिद्वार नगर निगम कर्मचारियों की पूरी परीक्षा ली। मूसलाधार बारिश ने नगर निगम कर्मचारियों के सामने तमाम चुनौतियां पेश की। नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार ने इस चुनौती से निबटने के लिए रणनीति बनाई। उनके निर्देशों पर नगर निगम अधिकारियों ने कनखल, उत्तरी हरिद्वार, भूपतवाला, ज्वालापुर और रानीपुर मोड़ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी। बारिश थमने का इंतजार किए बिना कर्मचारियों ने नालों की सफाई, पानी की निकासी और रास्तों को साफ करने का काम जारी रखा। जिसके चलते जनता को राहत मिल सकी।

मेयर का फील्ड निरीक्षण

मेयर किरण जैसल खुद मैदान में उतरीं और जलभराव प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही दिशा-निर्देश दिए और कहा कि शहरवासियों को किसी भी हाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारी टीम हर समय अलर्ट पर है।÷

स्थानीय लोगों ने की सराहना

बरसात से परेशान आमजन ने निगम प्रशासन की इस तत्परता की खुलकर सराहना की। ज्वालापुर कटहरा बाजार निवासी व्यापारी नेता पुनीत गोयल ने कहा पहले थोड़ी बारिश में भी सड़कें तालाब बन जाती थीं, लेकिन इस बार पानी की निकासी काफी बेहतर रही। कनखल संदेशनगर निवासी सौरभ सारस्वत ने बताया हरिद्वार नगर निगम की टीमें तुरंत पहुंचीं, जिससे हमें घर से बाहर निकलने में परेशानी नहीं हुई। भूपतवाला के व्यापारी हरपाल सिंह ने कहा कि पहली बार देखने को मिला कि बरसात के बीच ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर खड़े होकर काम करा रहे थे। सीतापुर निवासी धूम सिंह मेमोरियल स्कूल के चेयरमैन मुकुल चौहान ने भी नगर निगम प्रशासन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपेक्षा से अधिक बारिश हुई। लेकिन निगम प्रशासन की टीम ने जनता को राहत पहुंचाने में पूरा सहयोग किया। जिसके चलते जलभराव से राहत मिल सकी।

हरिद्वार पुलिस ने ढूंढ निकाले खोए हुए 46 मोबाइल

पथ प्रवाह हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन रिकवरी कई उदास चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। इस अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उन्हें उनके स्वामियों को सौंप रही है। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस ने खोए हुए 46 मोबाइल फोन ढूंढकर उदास चेहरों पर खुशी लाने का काम किया है।

एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा ऑपरेशन रिकवरी के तहत चोरी/खोए मोबाइल की बरामदगी के लिए गठित सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से खोए हुए 46 मोबाइल फोन की रिकवरी की है, जिनकी कीमत लगभग 9,12,000/- रुपये है। ये मोबाइल फोन उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश व अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल की मिलने की आस खो बैठे मोबाइल स्वामियों द्वारा अपने मोबाइल सही सलामत हालत में पाकर हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद किया गया।

बरसात में टूटी सड़कों पर शुरू करें मरम्मत का कार्य: जिलाधिकारी

पथ प्रवाह हरिद्वार। भारी बारिश के चलते जनपद में क्षतिग्रस्त सड़कों का आकंलन कर मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये। कहा कि राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय कर जो भी कार्य किए जा रहे है उन कार्यों को समयावधि के अंतर्गत पूर्ण करें।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिशासी अभियंता लोनिवि, पीएमजीएसवाई और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि भारी वर्षा के कारण जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त हो गई हैं उनको तत्काल दुरुस्त करा जाए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह भी अपने-अपने क्षेत्रों की सड़कों का निरीक्षण करते हुए जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उनकी सूचना संबंधित सड़क विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभाग बी एवं सी श्रेणी में चल रहे है,उन्हें ए श्रेणी में आने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने कहाकि शासन द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृत की गई है यदि वो किन्हीं कारणों से संचालित नहीं हो रही हैं उसका पूर्ण विवरण अगली बैठक में दें। अधिकारियों से जनपद में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अपने-अपने कार्यालय एवं आस-पास क्षेत्रों में विशेष

स्वच्छता अभियान चलाने के लिए कहा। नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं जिला पंचायत के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रो में सफाई अभियान चलाने तथा जिन क्षेत्रों में कचरा एकत्रित हुआ है उसका उचित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि भारी वर्षा के कारण जनपद में जो भी परिसंपत्तियों, परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका संबंधित विभागों से आंकलन प्रस्ताव उपलब्ध कराएं, जिससे कि मरम्मत पर होने वाली व्यय धनराशि का आंकलन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी वित्त दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके सिंह, परियोजना निर्देशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश ,जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह,अधीक्षण अभियंता जल निगम एम मुस्तफा,अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, डीएसओ तेजबल सिंह,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

अगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लहराएगा भगवा- संजीव चौधरी

भाजपा जिला महामंत्री संजीव चौधरी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

पथ प्रवाह हरिद्वार। नवनियुक्त भाजपा जिला महामंत्री संजीव चौधरी का अपने आवास पहुँचने पर कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान फूल माला पहनाकर और ढोल नगाड़े के बीच आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता को सम्बोधित करते हुए नवनियुक्त जिला महामंत्री संजीव चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पांचों सीटों पर भगवा लहराएगा। भाजपा ने जो विश्वास मुझ पर जताया है मैं उस पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। आगामी विधान सभा चुनाव में जिले की पांचो सीटों पर

भाजपा का परचम लहराए और प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने इसके लिए रात दिन कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करूंगा। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज प्रदेश उन्नति और विकास के मार्ग पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले चुनाव में फिर से धामी सरकार बनेगी। राज्य को देश में आदर्श राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात जुटे हुए हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि अपने बाल्य काल से ही पार्टी और देश धर्म की सेवा में जुटे संजीव चौधरी को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। कार्यकर्ताओ को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष नगर पालिका शिवालिक नगर राजीव शर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा से लेकर और जिला महामंत्री बनने तक अनेक पार्टी आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले संजीव चौधरी को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर भी वो खरा उतरेंगे।

हरिद्वार को मिलेगा अत्याधुनिक रोडवेज बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

पथ प्रवाह, संवाददाता

तीर्थनगरी हरिद्वार में नया रोडवेज बस स्टैंड बनाने की दिशा में शासन और जिला प्रशासन ने ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। जगजीतपुर क्षेत्र में करीब 40 बीघा भूमि पर अत्याधुनिक रोडवेज बस स्टैंड विकसित करने की योजना है। यहाँ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक इंतज़ार कक्ष, शौचालय, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और रोडवेज एआरएम विशाल चंद्रा ने जगजीतपुर में डीएवी स्कूल के सामने प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और भूमि संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। विदित हो कि दशकों पुराना हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड मात्र 14 बीघा भूमि में संचालित हो रहा है, जिसके बाहर टैक्सी स्टैंड और यूनियनों के कार्यालय होने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। नए बस स्टैंड के निर्माण से यात्रियों को न सिर्फ आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुचारु होगी।

संपादकीय

भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा टेक्स सिस्टम

भारत की कर प्रणाली देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। सरकार का यह तर्क कि टैक्स वसूलना देश के विकास और जनहित के लिए आवश्यक है। यह पूरी तरह सही प्रतीत नहीं होता है। असलियत यह है कि देश का टैक्स सिस्टम ना केवल जटिल है। बल्कि हर स्तर पर केन्द्र, राज्य, स्थानीय संस्थाओं एवं शुल्क के रूप में जिस तरह से टेक्स वसूल किया जा रहा है। उससे आम आदमी परेशान हो गया है। तरह-तरह के टेक्स आम नागरिक और व्यवसायी दोनों के लिए भारी बोझ बनता जा रहा है। भारत की टैक्स प्रणाली के नियम और कानून इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, सरकार के उच्च पदों पर बैठे नेता और अधिकारी कर प्रणाली का उपयोग भ्रष्टाचार और नागरिकों को दबाने के लिए करते हैं। विशेषकर मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमी इस तंत्र की चपेट में आकर सदैव मानसिक और आर्थिक दबाव में रहते हैं। जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। जीएसटी ने सभी की कमर तोड़ दी है। हाल ही में भारत की कर प्रणाली के संबंध में जो तथ्य सामने आया है, उससे स्पष्ट है, भारत में एक करोड़ रूपए कमाने वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय या कमाई का लगभग आधे से ज्यादा कमाई को टैक्स और अन्य सरकारी शुल्क में भुगतान करना पड़ता है। भारत में यदि 1 करोड़ रूपए कमाते हैं, तो टैक्स, जीएसटी, मेंटेनेंस, रेंट, कर्मचारी वेतन व अन्य खर्चों के बाद आपके पास बड़ी मुश्किल से मात्र 35 लाख रूपए की बचत होती है। दूसरी ओर, दुबई जैसे देशों में सरकारी कर नाममात्र के है। जिसके कारण दुबई की आर्थिक प्रगति बड़ी तेजी के साथ हो रही है। इसका लाभ वहां की सरकार और आम जनता को समान रूप से मिल रहा है। दुबई जैसे देश में जो भी काम धंधा करके कमा रहा है। उसका पूरा पैसा उसके पास रहता है। वह अपनी मनमर्जी से खर्च करता है। उस खर्च पर टेक्स या सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होने से लोग बड़ी कमाई भी करते हैं, और कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च भी करते हैं। वहां पर लोगों का स्वाभिमान और आत्मविश्वास दोनों ही बना रहता है। भारत मे वर्तमान टैक्स प्रणाली के दुष्परिणाम के कारण, भारत की उच्च कमाई वाले उद्योगपति और व्यवसायी विदेश में निवेश करने लगे हैं। जिससे देश का रोजगार और निवेश लगातार कम हो रहा है। सबसे दुखद पहलू यह है कि सरकारी कर प्रणाली आम जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि कारोबारियों से अधिक धन वसूलने के लिए डिजाइन की गई है।

हिमालय दिवस पर विशेष रिपोर्ट

रक्षा-सूत्र आंदोलन के प्रणेता सुरेश भाई ने दी चेतावनी अगर विकास की दिशा नहीं बदली तो हिमालय बनेगा जलवायु शरणार्थियों की धरती

हिमालय दिवस पर पर्यावरणविद् सुरेश भाई का बयान : लगातार आपदाएँ चेतावनी, अनियंत्रित विकास पर लगाम जरूरी

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। हिमालय दिवस के अवसर पर पर्यावरणविद् सुरेश भाई ने कहा कि आपदा ने हिमालय और उसकी नदियों के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों तरह की आपदाएँ चर्चा का विषय बन चुकी हैं। मध्य हिमालय उत्तराखंड से बह रही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ और भूस्खलन का रौद्र रूप सब देख चुके हैं। पिछले डेढ़ दशक में भागीरथी और अन्य नदियों पर सन् 2010, 2011, 2012, 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की ऋषिगंगा त्रासदी, 2023 का जोशीमठ धंसाव, 2024 की बालगंगा आपदा और 2025 में आई भीषण जलप्रलय भविष्य के लिए बेहद निराशाजनक संकेत दे रही है। इन विनाशकारी आपदाओं ने न केवल हिमालय की सेहत बिगाड़ी है बल्कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन भी संकट में डाल दिया है। सुरेश भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में माना है कि हिमाचल प्रदेश में आ रही प्राकृतिक आपदाएँ अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों का परिणाम हैं और अगर इसे रोका नहीं गया तो हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है। यही स्थिति उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2017 में नैनीताल उच्च न्यायालय ने गंगा को जीवित इकाई का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में विकास की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उस पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि नदियों के किनारों से गुजर रही सड़कों का चौड़ीकरण, पर्यटन स्थलों का विस्तार, सुरंग परियोजनाओं और बड़े निर्माण कार्यों का मलबा सीधे नदियों में फेंका जा रहा है। इसने नदी के आर-पार के पर्वतों को घायल स्थिति में ला दिया है। वनों की बेरहमी से कटाई सबके सामने है, लेकिन पेड़ों के कटान को रोकने की आवाजें भी संकट में पड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में नदियों के उद्गम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों का व्यावसायिक दोहन चल रहा है। इसका विरोध तो हो रहा है, लेकिन अनियोजित विकास के नाम पर इन आवाज़ों को अनसुना कर दिया जाता है। नतीजतन बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों के लट्ठे बहकर नदियों में आ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि भागीरथी घाटी के धराली और हरसिल में आई आपदा के दौरान देवदार के पेड़ों ने मिट्टी को थाम रखा है, अगर इन्हें भी काट दिया गया होता तो घाटी में और बड़ा संकट खड़ा हो जाता। इसलिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में चौड़ी सड़कें बनाना आपदा को न्योता देना है। सुरेश भाई ने कहा कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रहे विस्फोट और जेसीबी मशीनें भूकंप से हिले पर्वतों की रीढ़ को और कमजोर कर रही हैं। बरसात के दौरान वही मिट्टी भूस्खलन के रूप में बस्तियों को तबाह कर देती है। मौसम विज्ञानी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन प्रभावित लोग समय रहते सतर्क नहीं हो पाते। उत्तरकाशी में 2012 से भागीरथी इको सेंसेटिव जोन की शर्तों को लागू नहीं किया गया है। यदि नियमानुसार महायोजना बनाई जाती तो आपदा को काफी हद तक रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस अनिश्चितता और अनियमितता ने हिमालयी नदियों के तटों और ग्लेशियरों से आ रहे गादेरों के मुहाने पर लोगों की बस्तियों को खतरे में डाल दिया है। इस मानसून में यमुना और भागीरथी पर तीन-तीन बार झीलों का बनना इसका सबूत है, जिसके कारण अपार जनधन की हानि हुई है। उत्तराखंड सरकार ने 5700 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यही धन सीमांत किसानों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सकता था। सुरेश भाई ने स्पष्ट कहा कि यदि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी समझ में नहीं आया तो आने वाले समय में हिमालय के लोग जलवायु शरणार्थी की स्थिति में पहुँच जाएंगे।

समस्त मंगलों का मूल है 15 दिवसीय श्राद्ध पक्ष

डॉ राघवेंद्र शर्मा

अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले वंशजों के लिए यह एक शुभ समाचार ही है, कि आश्विन माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। जाहिर है प्रतिपदा से लेकर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक पूरे 15 दिन का यह महोत्सव आस्था का महापर्व है। कुछ लोग इस पखवाड़े को अशुभ बताते हैं, इस तर्क के साथ कि इन दिनों कोई शुभ कार्य करना ही नहीं चाहिए अथवा शुभ कार्य नहीं किया जाता। यहां एक बात जानने योग्य है, वह यह कि किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि कनागतों में शुभ कार्य वर्जित हैं या फिर यह पक्ष अशुभकारी है। बल्कि वर्तमान पीढ़ी से अपेक्षा यह की गई है कि कम से कम इन 15 दिनों तक तो हम अपने पितरों के प्रति समर्पित बने रहें । यही वह विचार है जो स्थापित करता है कि काम धंधे और अन्य लाभ हानि के प्रसंग तो साल भर चलते ही रहेंगे। लेकिन पितरों के हिस्से में तो साल के केवल 15 दिन ही आते हैं। अतः इन दिनों उनके प्रति समर्पित रहें।यही वजह है कि अन्य कार्यों की अपेक्षा आस्थावान लोग श्राद्ध पक्ष में पितरों के पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य आदि कार्यों में संलग्न रहना ही उपयुक्त समझते हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथो के अनुसार इन 15 दिनों तक पितरों को मृत्यु लोक में आवागमन की छूट रहती है। यह इस ईश्वरीय सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने वंशजों के बीच पहुंचते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि वह पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, भूखों को भोजन कराएं, पिंडदान एवं तर्पण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दें। यह अपेक्षा इसलिए भी रहती है, क्योंकि इस दौरान वंशजों द्वारा जो त्याग किया जाता है, वह पितरों को आगामी ऊर्जा के रूप में उपलब्ध बना रहता है। इस प्रकार वे पूर्वज जिन्हें कोई देह नहीं मिली है और नरक, स्वर्ग, मृत्यु लोक से विलग हैं तथा पितृ लोक में स्थान पाए हुए हैं। वे साल भर संतुष्ट रहते हैं। ऐसा होने पर पितरों का आशीर्वाद वंशजों को प्राप्त होता है। फल स्वरुप वर्तमान पीढ़ी के सभी प्रकार के पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके जो परिणाम देखने को मिलते हैं वह इस सत्य को प्रतिपादित भी करते हैं कि पूर्वजों को नियमित पानी देने वाले वंशज दैविक एवं पैशाचिक बाधाओं से उबरने लगे हैं। हिंदू धर्म में एक भ्रामक जानकारी यह भी है कि पितरों का श्राद्ध कर्म केवल पुरुष वंशजों द्वारा ही किया जा सकता है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। इसका प्रमाण त्रेता युग में सीता जी द्वारा अपने पिता राजा श्री शीलध्वज यानि कि जनक जी का पिंडदान करने के प्रसंग से मिलता है। ग्रंथ बताते हैं कि धर्म ने पुत्री सीता द्वारा दिए गए पिंडदान को इतना महत्व दिया कि स्वयं राजा जनक को पिंड प्राप्त करने सीता जी के समक्ष सशरीर उपस्थित होना पड़ गया। श्राद्ध एवं पितृ पूजन कितना जरूरी है यह भी जानने योग्य है। दानवीर कर्ण को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति केवल इसलिए नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों का तर्पण किया ही नहीं था। किंतु पुण्यों का प्रारब्ध अर्जित था, इसलिए पुनः मृत्यु लोक में आने की पात्रता मिली। इन्हीं श्राद्ध पक्ष के दौरान दानवीर कर्ण पृथ्वी पर आए और पूरे 15 दिनों तक अपने समस्त पूर्वजों के सम्मुख हुए। उन्होंने अपने श्रम से अर्जित धन-धान्य से पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य किए। इससे पितृ लोक में मौजूद पूर्वज प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद प्राप्त होने पर कर्ण को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो पाया। इन प्रसंगों से हम सीख सकते हैं कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में प्रत्यक्ष रहने वाले श्राद्ध पक्ष हर दृष्टि से मंगलो के मूल ही हैं।

जीएसटी को कम करने से देश की प्रगति रूक सकती है

संजय गोस्वामी

आज सभी जी एस टी को कम करने से बहुत से लोग तारीफों के पूल बांध रहें हैं लेकिन ऐ देश की प्रगति को धीमा कर सकता है टैक्स को कर कहते हैं जो राष्ट्र के निर्माण में बेहतर करने के लिए रक्षा,शिक्षा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व विकास, स्वच्छता पिने के पानी को उपलब्ध कराने व खाने पिने के चिजों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने बाल कल्याण योजनाओं को चलाने व अन्य सामरिक संस्थानों को मदद करने के लिए आपदाओं से निपटने व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योजनाओं को चलाने के लिए तरह-तरह के कर लगातीं हैं। कर प्रायः धन (mone4) के रूप में लगाया जाता है किन्तु यह धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। कर दो तरह के हो सकते हैं - प्रत्यक्ष कर (direct tax) या अप्रत्यक्ष कर (indirect tax)। प्रत्यक्ष कर वह कर यानि टैक्स है जो सीधे उन लोगों से एकत्र किया जाता है जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जैसे कि आयकर, संपत्ति कर, संपत्ति कर आदि, जबकि एक अप्रत्यक्ष कर वह होता है जिसे आप जब भी कुछ सामान खरीदते हैं या कुछ सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आप भुगतान करते हैं। अप्रत्यक्ष करों में मूल्य वर्धित कर (वैट), बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आदि शामिल हो सकते हैंएक तरफ इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है वहीं इसे सरकार को चलाने के लिये आधारभूत आवश्यकता के रूप में भी समझा जा सकता है।जीएसटी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, सरकारी राजस्व बढ़ाता है और निर्माताओं पर कर का बोझ कम करता है, उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करता है और भारत की राजकोषीय स्थिति को लगातार मजबूत करता है और अप्रत्यक्ष कराधान को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। 2024-25 में, जीएसटी ने ?22.08 लाख करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम सकल संग्रह दर्ज किया, जो साल-दर-साल 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। औसत मासिक संग्रह ?1.84 लाख करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 के लिए भारत का रक्षा बजट ?6,81,210.27 करोड़ है, जो पिछले वर्ष से 9.5% की वृद्धि है, जिसका उद्देश्य सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ाना, घरेलू रक्षा उत्पादन को मजबूत करना और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का समर्थन करना है। इस आवंटन में पूंजी अधिग्रहण और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण धनराशि शामिल है, जिसमें आधुनिकीकरण बजट का 75% घरेलू खरीद के लिए निर्धारित है।अतः अतः आज जीडीपी को सुधारने व इकोनॉमी को पटरी पर लाने के जरुरी है सरकार के पास पैसा हो जो देश के विकास के लिए कारोबारियों से टैक्स के रुप में प्राप्त करती है वो देश की प्रगति हेतु लिया जाता है जिससे सेना का बजट,विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास, गरीबों को राशन, स्वास्थ्य, बीमा, रोजगार और महिलाओ की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाती है आज रक्षा अंतरिक्ष, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में देश आत्मनिर्भर हो रहा है इसके लिए कर का महत्वपूर्ण योगदान है अतः जी एस टी को कम करना देशहित में नहीं है देश के प्रगति रक्षा और गरीबों के कल्याण हेतु कर को कम करना उचित नहीं है.कर करदाता द्वारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो कि रक्षा व सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके नए युवकों को रोजगार प्राप्त करने में सहायक होता है तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में भी सहायक होता है।

भारत खूबसूरत मानवीय बोलियों, भाषाओं का एक विश्वप्रसिद्ध अभूतपूर्व संगम

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

भारत माता की गोद में एक से बढ़कर एक अनेक ऐसी खूबसूरत उपलब्धियां, हजारों वर्ष पूर्व से उपलब्ध है जिनकी अणखुट संरचना, प्राकृतिक खूबसूरती, विशाल भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं के साहित्यग्रंथों सहित अनेक अपार क्षमता वाली बौद्धिक संपदा का विशाल भंडार देख संपूर्ण विश्व हैरान था!! जिस पर नज़र लग गई थी!! जिससे हजारों वर्षों की गुलामी से आजादी के बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ। साथियों फ़िर भी हम अपनी मेहनत, लगन से फिर अपनी ताकत, ज़ाज़बे और जांबाज़ी के साथ वैश्विक पटल पर प्रमुख हस्ती के रूप में अपने हर क्षेत्र की समृद्धि व ताकत के आगाज़ के साथ वैश्विक पटल पर अहम स्थान रखते हैं, जिसे देखकर विश्व की नजरें फिर भारत की ओर आकस्मिकता से देश भारत का लोहा मान रही है। आज भारत उस स्थिति में है जहां भारत की ओर नज़र लगाने वाले को हज़ार बार सोचना पड़ेगा!! यह है हमारा आज का भारत!!! साथियों बात अगर हम अपनी संस्कृति, विशाल मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के साहित्यग्रंथों की करें तो यह हमारी पहचान है। यूं तो भारत में बावीस भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है परंतु पूरे भारत की बात करें तो यहां भाषाएं व उपभाषाएं हजारों की संख्या में होंगी, जिसकी रक्षा करना और विलुप्तता से बचाने की ज़वाबदारी हमारे आज के युवाओं के ऊपर है क्योंकि आज हमारे देश की 68 प्रतिशत आबादी युवा है और इस युवा भारत के युवाओं को ही हमारी संस्कृति, भाषाओं को जीवित रखना है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना होगा और अपने समाज, घर, क्षेत्र में अपनी मातृभाषा में बात करना होगा ताकि उसे हम विलुप्तता से बचा सके!!! आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचलन कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर के युवाओं में इसका क्रेज अधिक महसूस किया जा रहा है जो बड़े शहरों से होकर अब हमारे छोटे शहरों गांवों में भी फैलने की संभावना बढ़ गई है। जिसका संज्ञान बुजुर्गों को लेना होगा और युवाओं को अपनी मातृभाषा में बोलने, संस्कृति, साहित्यग्रंथों, भाषाओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराकर उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देना होगा ताकि भारतीय धरोहर को विलुप्तता से बचाया जा सके। हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई बार देखा, पड़ा, वह सुना है कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति का संज्ञान इस भाषाई क्षेत्र की ओर बहुत अधिक है!! और हर मौके पर इस दिशा में सुझाव, मार्गदर्शन, अपील, प्रोत्साहन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जो काबिले तारीफ है!!! साथियों बात अगर हम माननीय उपराष्ट्रपति की दिनांक 12 दिसंबर 2021 को एक विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस समारोह को संबोधन करने की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने इस संबंध में विश्वाविद्यालयों से भारतीय भाषाओं में उन्नत अनुसंधान करने तथा भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में सुधार लाने का सुझाव लाने की अपील की, जिससे कि उनकी व्या पक पहुंच तथा शिक्षा क्षेत्र में उपयोग को सुगम बनाया जा सके।

एक नजर

आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत हरबर्टपुर में शुरू हुई तीन दिवसीय कार्यशाला

देहरादून। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''आदि कर्मयोगी अभियान'' के अन्तर्गत आज सोमवार को पी.सम. श्री राजकीय इन्टर कॉलेज, हरबर्टपुर देहरादून में तीन दिवसीय जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला (डीपीएल) का शुभारम्भ किया गया। जिसमें भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से रवि शेखर, अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विकम सिंह ने दीप प्रवजलन कर प्रयोगशाला का शुभारम्भ किया। ''आदि कर्मयोगी अभियान'' के अन्तर्गत जनपद-देहरादून के 04 विकास खण्डों के कुल 41 गांवों का चयन किया गया है जिसके अंतर्गत सभी 41 गाँवों में निवासरत समस्त जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित समस्त लोक कल्याणकारी योजना से शत-प्रतिशत लाभान्वित किया जाना है। प्रयोगशाला में राज्यस्तरीय, जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ ही सम्बन्धित विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों व संबंधित विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया गया। प्रयोगशाला में राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा ''आदि कर्मयोगी अभियान'' के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किए जाने हेतु संबंधित विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को जानकारी दी गई।

सात दिवसीय नि :शुल्क हीलिंग कैम्प का भव्य समापन

कैम्प में प्राणिक हीलिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं का किया उपचार

देहरादून । सारथी विहार में सात दिवसीय निःशुल्क हीलिंग कैम्प का भव्य समापन किया गया। हीलिंग कैम्प देहरादून में ऑल इंडिया योग विद्या प्राणिक हीलिंग के दून सेंटर की शैल उनियाल के नेतृत्व में कैम्प का आयोजन किया गया। इस कैम्प में आये हुए सैकडों लोगों की निःशुल्क हीलिंग की गई। इस दौरान निःशुल्क हीलिंग कैम्प में प्राणिक हीलिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं का उपचार किया गया । इस अवसर पर प्राण शक्ति, प्राणिक हीलर्स आम जनमानुस की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं। जो भी लोग इस कैम्प में आए, सभी बहुत खुश होकर एवं अपनी समस्याओ का समाधान पाकर गए। इस अवसर पर कैंट विधानसभा की विधायक सविता कपूर ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि इस प्रकार के कैम्प और ज्यादा होने चाहिए जिससे मानवता का भला होता है। कैम्प में आकर एवं हीलिंग प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि शैल उनियाल निरंतर प्राणिक हीलिंग के माध्यम से समाज एवं जन कल्याण के कार्य में निरंतर लगी हुई है और इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।

तंबाकू निषेध दिवस पर स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों ने निकाली जागरूकता रैली

देहरादून। राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में तंबाकू निषेध दिवस पर स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं आम जन ने जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तंबाकू का सेवन हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है और इसके दुष्प्रभावों से हमें बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू में कई हानिकारक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिष्ट ने कहा कि इसके सेवन से कैंसर, हृदय रोग, और श्वसन समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के आसपास रहने वाले लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. स्वामी एस चंद्रा ने कहा कि तंबाकू से बचने के लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए। हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए।

महंत इन्दिरेश अस्पताल में हर्षोल्लास से मनाया गया वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस

देहरादून। महंत इन्दिरेश अस्पताल में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। इस दौरान पोस्टर प्रतियोगिताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान गुरु राम राय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पैरामैडिकल एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने बढ़चढ़कर भागीदारी की। महंत इन्दिरेश अस्पताल के ऑडिटोरियम में गुरु राम राय विश्वविद्यालय के को-ऑर्डिनेटर डॉ. आर.पी सिंह, अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल मलिक, चिकित्सा अधीक्षक डॉ अजय पंडिता, डीन डॉ. कीर्ति सिंह और फिजियोथेरेपी विभागाध्यक्ष डॉ. शारदा शर्मा व डॉ. नीरज कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस वर्ष वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस की थीम हेल्थ एजिंग (स्वस्थ बुढ़ापा) रही। इसी कड़ी में पैरामैडिकल छात्र-छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से यह संदेश दिया कि नियमित फिजियोथेरेपी से स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन संभव है। इस अवसर पर पोस्टर प्रदर्शनी में दर्शकों को उम्र के हर पड़ाव पर फिट रहने के उपायों से अवगत कराया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में बीपीटी के शोहेब ने प्रथम, बीपीटी की निधि ने द्वितीय और सान्या ने तृतीय पुरस्कार जीता। पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। महंत इन्दिरेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेन्द्र दास महाराज ने कार्यक्रम आयोजकों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एमपीटी तृतीय वर्ष की छात्राओं ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। बीपीटी प्रथम वर्ष की छात्रा दिव्या ने कविता के माध्यम से फिजियोथेरेपी की महत्ता को हृदयस्पर्शी शब्दों में रखा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने स्वस्थ बुढ़ापा विषय का मार्मिक चित्रण किया।

आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए: मुख्यमंत्री

बरसात के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और चारधाम यात्रा को सुचारु कराने पर जोर

सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान की विस्तृत तैयारी करने के निर्देश

अस्पतालों की व्यवस्थाओं, जन सेवाओं को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन एवं जनसुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव मोड में कार्यरत रहे। वर्षा काल तक राहत सामग्री एवं ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपदा प्रभावितों के ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। फसलों, पेयजल लाइन एवं सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। नदी-नालों के पास निर्माण की अनुमति पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाए। प्रतिबंधों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को मानकानुसार त्वरित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करें और विभिन्न व्यवस्थाओं का आकलन करें। डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित रोगों से बचाव के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की शीघ्र बैठक करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अनधिकृत आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन जारी करने वालों पर नियमित कार्रवाई की जाए। बाहरी व्यक्तियों व संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए।सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग और सख्ती बढ़ाई जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। गौवंश के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के बाद पुनर्निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में तेजी लाई जाए। सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जाए। गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून के बाद चारधाम यात्रा सतर्कता के साथ सुचारू रूप से संचालित हो। श्रद्धालुओं को खराब मौसम की जानकारी समय पर मिल जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद की मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं चालू कार्यों की रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। ग्राम स्तर पर चैपाल कार्यक्रम, जिलास्तरीय जनसुनवाई, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों एवं बहुउद्देशीय शिविरों का नियमित आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की विस्तृत तैयारी की जाए। सेवा, स्वच्छता और जनसुविधा की थीम पर कार्य किए जाएं। जनपदों में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ प्रत्येक सप्ताह एक दिन स्वच्छता कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वयं प्रतिभाग करें। क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द सुचारु करने के साथ ही अभियान के तहत सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 1905 सीएम हेल्पलाइन और 1064 एंटी करप्शन कैंपेन की कार्यवाही निरंतर जारी रहे। आपदा की चुनौतियों से पार पाने के लिए डिजास्टर वालंटियर, संकट मोचन दल एवं जनपद स्तर पर मॉक ड्रिल कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत प्रदान किए जा रहे विभिन्न प्रमाण पत्रों को आवेदनकर्ता जिस भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) में मांगते हैं, उसी भाषा में उपलब्ध कराया जाए। नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया में सम्मिलित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

जनता दरबार में आई 125 समस्याएं, अधिकतर का मौके पर समाधान

सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण की शिकायत, जिला प्रशासन द्वारा सख्त प्रवर्तन कार्रवाई तय

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी गई। दूर दराज से पंहुचे लोगों ने अवैध अतिक्रमण, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल, भूस्खलन से भवनों को बना खतरा, घरेलू एवं निजी भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदि से जुड़ी 125 शिकायतें रखी। जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। हर्रवाला में सार्वजनिक रास्ते में खंबे लगाकर अवैध रूप से तारबाड और कब्जा करने की शिकायत पर उप नगर आयुक्त तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वही भाटगढ़ी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। बदामवाला में सड़क किनारे पानी की नाली बंद कर सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं अठूरवाला निवासियों ने सड़क से एलटी विद्युत पोलों को शिफ्ट कराने की गुहार लगाई। टीएचडीसी कॉलोनी निवासियों ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत टीएचडीसी के मुख्य द्वार के सामने से गुजरने वाली सड़क पर उचित मानक एवं संकेतकों के साथ स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग पर लोनिवि व परिवहन विभाग को तत्काल समस्या का समाधान करने को कहा गया। ग्राम पुरोहितवाला की प्रधान ने बताया कि बारिश के कारण गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की समस्या हो रही है। जिस पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। ग्राम सभा कान्सवाली नौगांव में जल निगम द्वारा कनेक्शन देने के बावजूद भी चार माह से पानी नही आने की शिकायत दर्ज की। ग्राम पंचायत रैनापुर के प्रधान ने गांव के अंतर्गत कच्चे मकानों को प्रधानमंत्री आवास या आपदा राहत मद से पुनर्निर्माण कराने, क्षतिग्रस्त पंचायत भवन पुनर्निर्माण की बात रखी। जिस पर बीडीओ को पात्र लाभार्थियों का चयन करने को कहा गया। शिमला बाईपास रोड़ पर शेरपुर में निजी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने की शिकायत पर तहसीलदार को शीघ्र जांच करने को कहा गया। जागृति विहार निवासी व्यक्ति ने जमीन फ्रॉड की शिकायत करते हुए बताया कि उनसे 05 लाख का बयाना लेने के बाद भी उनके नाम रजिस्ट्री नही की जा रही है। शिकायत पर सीओ पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए। मोथरोवाला निवासी विधवा महिला ने ठेकेदार पर पैसा लेने के बाद भी मकान का काम पूरा न करने की शिकायत दर्ज की। रतन सेठी ने हिट एंड रन मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई न होने की शिकायत पर एसएचओ पुलिस को त्वरित जांच के निर्देश दिए गए। विकासनगर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने पुत्र व पुत्रवधू द्वारा अभद्रता एवं दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में सीओ पुलिस को तत्काल मामले की जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकृत किए जाने की शिकायत पर एलडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। इस दौरान फरियादियों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम समस्याएं रखी गई। जनता दरबार में अपर नगर आयुक्त रजा अब्बास, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपूर्वा, एसडीएम विनोद कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

राजधानी में द्वितीय उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड का आयोजन छह दिसम्बर को: विनोद कुमार

देहरादून। उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड के संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने कहा है कि द्वितीय उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड आगामी छह दिसम्बर को प्रदेश की अस्थाई राजधानी देहरादून में किया जाएगा। यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि द्वितीय उत्तराखंड फिल्म अवार्ड में एक जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2024 तक की सिनेमाघरों में प्रदर्शित फिल्मों को अवार्ड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दो वर्षो के मध्य रिलीज हुई फिल्मों के निर्माता आज से आगामी पांच नवम्बर तक अपनी फिल्मों के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि द्वितीय उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड दून के कलाकारों व फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेता, अभिनेत्रियों, संगीतकारों, गायकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कला प्रेमियों को सम्मानित किया जाएगा। गुप्ता ने कहा है कि अभिनेता हेमंत पांडे को चयन समिति में नामित किया गया है और वहीं अभिनेता को उत्तराखंडी फिल्मों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस अवसर पर अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा है कि विनोद कुमार गुप्ता द्वारा आयोजित उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड एक सराहनीय कदम है जिससे उत्तराखंडी बोली में बनने वाली फिल्मों के कलाकार व टेक्नीशियन खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन कार्य कर सकेंगें और उत्तराखंडी फिल्मों की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए आगे आना होगा।

दैनिक
पथ प्रवाह
हरिद्वार, मंगलवार 09 सितंबर 2025

धराली-हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुँची अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम, प्रभावितों के नुकसान की रिपोर्ट जल्द जाएगी केंद्र को

धराली–हर्षिल में केंद्रीय टीम ने मकानों, सड़कों, पुलों और फसलों की क्षति का लिया जायजा, प्रभावितों से की बातचीत

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

धराली/उत्तरकाशी। धराली-हर्षिल क्षेत्र में हाल में आई आपदा के बाद सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम (ढ्ढरूष्टञ्ज) ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया। टीम का उद्देश्य आपदा के दौरान हुए नुकसान का आकलन करना, राहत-पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करना और प्रभावितों की समस्याओं को समझना रहा।

टीम का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना ने किया। उनके साथ निदेशक वित्त शैलेश कुमार, मुख्य अभियंता पंकज सिंह और उपनिदेशक विकास सचान शामिल रहे। हर्षिल आर्मी हेलीपेड पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल ने टीम का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान जनपद में हुई जनहानि, मकानों, होटलों, बगीचों, फसलों और व्यवसायों को हुए

नुकसान के विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए।

प्रभावित गाँवों का किया दौरा

टीम ने धराली, मुखवा और हर्षिल गाँवों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने क्षति का आकलन करने के लिए स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई। प्रभावित लोगों ने टीम के समक्ष अपने दुख-दर्द और नुकसान की जानकारी साझा की। उन्होंने मकानों, व्यवसायों और बगीचों की क्षति के अलावा रोजगार, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति पैकेज जल्द दिए जाने की मांग रखी।

बुनियादी ढाँचे और आजीविका का लिया जायजा

केंद्रीय टीम ने क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, पेयजल-बिजली लाइनों और अन्य बुनियादी ढाँचे का जायजा लिया। साथ ही कृषि भूमि, फसलें, पशुधन और स्थानीय आजीविका से जुड़ी क्षति का आकलन भी किया। टीम ने आपदा के दौरान भोजन, पानी, चिकित्सा और अस्थायी आश्रयों की उपलब्धता जैसी राहत कार्यों की जानकारी भी ली।

केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट

टीम लीडर आर. प्रसन्ना ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से आपदा प्रभावितों की परिसंपत्तियों और आजीविका को हुए नुकसान का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर राहत पैकेज घोषित किया जाएगा।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने इसे प्रभावितों के लिए राहत का महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि केंद्रीय टीम की सिफारिशें सरकार तक पहुँचेंगी और उसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे प्रभावितों के पुनर्वास और जनजीवन की बहाली में तेजी आएगी।

जिला प्रशासन के अधिकारी भी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल, एडीएम मुक्ता मिश्र, एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई संजय राज, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल, सीएमओ बीएस रावत, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल मनोज गुसाईं सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय िम का यह दौरा आपदा प्रबंधन, पुनर्निर्माण और प्रभावितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एक नजर

विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस, जाने क्या है इसका महत्व

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हर साल 7 सितंबर को विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस मनाता है। इस वर्ष का विषय था परिवार- देखभाल का केंद्र। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) एक दुर्लभ और क्रमिक रूप से बढ़ने वाली बीमारी है, जो मांसपेशियों को धीरे-धीरे कमज़ोर कर देता है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और गतिशीलता, श्वास और हृदय की कार्यप्रणाली को धीरे-धीरे प्रभावित करता है। इस स्थिति से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय पर हस्तक्षेप, जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक समावेश आवश्यक है।

इस अवसर पर देश भर में विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान कर सकता है कोलेस्ट्रॉल

नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है–यह एक अदृश्य क्वांटम गुण है जो ऊर्जा कुशल अगली पीढ़ी के स्पिन्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में योगदान दे सकती है।

कोलेस्ट्रॉल वसा समान पदार्थ है और सामान्य रूप से हृदय रोगों से संबंधित होता है, सुपरमोलेक्यूलर आधारित स्पिनट्रोनिक सामग्री बनाने के लिए एक आदर्श प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह इसके आंतरिक हाथतापन (चिरालिटी) एवं लचीलापन के कारण आणविक गुणों पर सटीक नियंत्रण को सक्षम बनाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के वैज्ञानिकों ने भविष्य की क्वांटम तकनीकों और स्पिन्ट्रोनिक अनुप्रयोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल-आधारित नैनोमैटेरियल्स को नवीन प्लेटफार्मों के रूप में पेश किया है। ये सामग्री इलेक्ट्रॉनों के घुमाव को नियंत्रित कर सकती हैं, यह एक क्वांटम विशेषता है जो अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। धातु आयनों को कार्बनिक संरचना के साथ मिलाकर, डॉ. अमित कुमार मंडल के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने साबित किया है कि धातु आयनों के प्रकार और सांद्रता को समायोजित करके एक पदार्थ अपने चुंबकीय स्पिन अभिविन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को कितनी अच्छी तरह से अलग कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल को विभिन्न धातु आयनों के साथ मिलाकर, शोधकर्ताओं ने नैनोमैटेरियल्स बनाया है जो चयनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन स्पिन को छानते हैं।

नागरिक जागरूकता, डिजिटल पहुंच और वित्तीय जागरूकता सच्ची साक्षरता के मुख्य बिंदु हैं : मंत्री जयंत चौधरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (आईएलडी) 2025 समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन, मिज़ोरम के शिक्षा मंत्री डॉ. वनलालथलाना और डीओएसईएल के सचिव संजय कुमार के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, एनसीटीई, एनआईओएस, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी शिक्षक, शिक्षार्थी, नव-साक्षर और अन्य हितधारक भी शामिल हुए।

इस वर्ष के समारोह की विषय वस्तु थी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, जिसमें देश भर में पढ़ने, लिखने, अंकगणित और आजीवन शिक्षण कौशल को सक्षम करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी ने चलाया विधिक व डिजिटल जागरूकता अभियान

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोमवार को अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर की अध्यक्षता सचिव सचिन कुमार ने की। इस दौरान छात्राओं को विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता जैसे समसामयिक विषयों पर भी जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। खासतौर पर महिलाओं, स्वयं सहायता समूह, किसानों और दैनिक वेतनभोगियों को इन विषयों पर जानकारी देकर उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी गई।

साक्षरता दिवस पर छात्राओं के बीच शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद-21) विषय पर निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, चित्रकला और नारा लेखन

जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। ÷न्याय और शिक्षा दोनों अधिकार हमारे÷ विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को शिक्षा और न्याय के महत्व पर गहन संदेश दिया। इसके अतिरिक्त एनसीसी, एनएसएस के छात्र-छात्राओं एवं पीएलवी ने पोस्टर और बैनर के साथ साक्षरता रैली भी निकाली।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस अवसर पर सभी विद्यालयों से आग्रह किया गया कि ÷वन चाइल्ड वन बुक÷ अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चा जरूरतमंद छात्र को एक पुस्तक दान करेगा। साथ ही पराविधिक कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि ÷न्याय और शिक्षा दोनों अधिकार हमारे÷ अभियान के तहत गांव-गांव में मूलभूत अधिकार, शिक्षा और न्याय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाए।

शिविर में सचिव सचिन कुमार, रिटेनर अधिवक्ता पदम दत्त जोशी, विद्यालय की अध्यापिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। आयोजन में लगभग 200 से अधिक लोगों ने सक्रिय भागीदारी की।

इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं और स्थानीय लोगों ने शिक्षा व न्याय के महत्व को समझते हुए संकल्प लिया कि वे इस अभियान को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।

आपदा प्रभावित राणाचट्टी में लगा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर, 118 लोगों को मिला लाभ

सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशों पर सोमवार को जनपद की बड़कोट तहसील के राणाचट्टी आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

आपदा के बाद स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए इस शिविर में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कुल 118 लोगों को शिविर से लाभान्वित किया गया। इनमें से 38 लोगों की बीपी जांच, 34 लोगों की शुगर जांच की गई। प्राथमिक उपचार हेतु 45 मरीजों को

दवाइयाँ वितरित की गई।

शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। एक गर्भवती महिला को आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गईं, वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर एक गर्भवती महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बड़कोट के लिए रेफर किया गया। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को आयरन व कैल्शियम की गोलियाँ वितरित की गईं तथा बच्चों को एलबेंडाजोल की खुराक दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रभावित इलाकों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर लगाने की पहल की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में स्वास्थ्य सुविधा मिलना बड़ी राहत है।

धराली आपदा की छाया में सादगी से मनाया गया दयारा बुग्याल का अढूंडी उत्सव, दूध-दही-मक्खन से खेली गई होली

ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। उत्तराखंड के मखमली बुग्यालों की खूबसूरती और ग्रामीण आस्था का संगम इस बार भी देखने को मिला, जब दयारा बुग्याल की हरी-भरी वादियों में पारंपरिक अढूंडी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। हालांकि, धराली आपदा की गहरी चोट के कारण इस साल उत्सव अपने तय समय से बीस दिन देर से और सादगी के साथ मनाया गया।

ग्रामीणों ने दूध, दही और मक्खन से एक-दूसरे को सराबोर कर खुशहाली की दुआएं मांगी। राधा-कृष्ण स्वरूप बने कलाकारों ने दही-हांडी फोड़कर उत्सव का शुभारंभ किया और वन देवियों व आराध्य देवताओं को विधिवत भोग अर्पित किया गया।

परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम

दयारा बुग्याल में हर साल भाद्रपद माह की संक्रांति पर यह उत्सव आयोजित होता है। इसे रैथल गांव और आसपास के ग्रामीण मिलकर आयोजित करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि सावन मास में दूध-दही और मक्खन को संजोकर रखना समृद्धि का प्रतीक है, और इन्हीं उत्पादों को देवताओं को अर्पित कर प्रकृति व मवेशियों की खुशहाली की कामना की जाती है। ढोल-दमाऊ की थाप पर रासो-तांदी नृत्य ने माहौल को और रंगीन बना दिया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि यह उत्सव केवल पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और समाज के बीच अटूट संबंध की मिसाल है।

धराली आपदा की छाया में फीकी पड़ी रौनक

दयारा पर्यटन समिति के अध्यक्ष मनोज राणा और सदस्य पृथ्वीराज राणा ने बताया कि इस साल धराली आपदा की वजह से यह उत्सव तय समय पर नहीं हो पाया। आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के बाद ग्रामीणों ने बीस दिन बाद इसे सादगी से आयोजित किया।

जहां सामान्य परिस्थितियों में हजारों की संख्या में पर्यटक और ग्रामीण शामिल होते हैं, वहीं इस बार दयारा बुग्याल में सीमित संख्या में ही लोग जुट पाए। रैथल गांव में धराली आपदा के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा और सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई।

बुग्यालों का सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व

दयारा बुग्याल (11,000 फीट ऊँचाई पर) हिमालय के सबसे सुंदर अल्पाइन घास के मैदानों में गिना जाता है। यह बुग्याल न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए आजीविका और संस्कृति का भी हिस्सा है। यहां सालभर मवेशियों के लिए घास उपलब्ध होती है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि बुग्यालों में ऐसे पर्व आयोजित करना ग्रामीणों को अपनी जड़ों से जोड़ता है और युवाओं को पारंपरिक संस्कृति से परिचित कराता है। साथ ही यह पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम भी है।

अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा बटर फेस्टिवल

पिछले कुछ वर्षों में बटर फेस्टिवल ने अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी इस पर्व का हिस्सा बनते रहे हैं। हालांकि इस साल आपदा के कारण विदेशी पर्यटकों की भागीदारी लगभग नगण्य रही।

फिर भी, ग्रामीणों का कहना है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अढूंडी उत्सव उनकी सांस्कृतिक पहचान है और इसे हर हाल में जीवित रखा जाएगा।

अढूंडी उत्सव केवल दूध-दही और मक्खन की होली भर नहीं, बल्कि यह हिमालयी ग्रामीण संस्कृति, प्रकृति के प्रति आस्था और सामाजिक एकजुटता का पर्व है। इस साल भले ही आपदा की छाया में यह आयोजन फीका रहा, लेकिन बुग्यालों की पवित्र वादियों में इसकी परंपरा एक बार फिर जीवित हो उठी।

59वां AWWA दिवस बरेली में धूमधाम से मनाया गया

पिथौरागढ़ के मेजर (सेनि.) ललित कुमार सिंह को मिला विशेष सम्मान

पथ प्रवाह, जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़। आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) का 59वां स्थापना दिवस मंगलवार को बरेली में बड़े उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष समारोह की अध्यक्षता AWWA की जोनल प्रेसीडेंट मिन्नी मिश्रा ने की। कार्यक्रम में मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले बच्चों और महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि,ड्ढ्ढ का मुख्य उद्देश्य सैनिक परिवारों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना है। पिथौरागढ़ के मेजर (सेनि.) ललित कुमार सिंह सम्मानित समारोह

में पिथौरागढ़ के मेजर ललित कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। वे मेजर्स एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक तथा पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के अध्यक्ष हैं। उन्हें गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने, पढ़ाई और रोजगार में सहयोग देने तथा जनपद की वीर नारियों और युद्ध विधवाओं के उत्थान में योगदान हेतु सराहना स्वरूप सम्मानित किया गया। मिन्नी मिश्रा ने मेजर ललित सिंह के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज सेवा में उनकी भूमिका प्रेरणादायी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि,ड्ढ्ढ भविष्य में भी उनके प्रयासों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

गरिमामय आयोजन

इस मौके पर बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी, सैनिक परिवार, छात्र-छात्राएँ और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैनिक परिवारों की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया।

जिलाधिकारी की अनूठी पहल

जनसुनवाई के दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं ने संभाली ष्स्की कुर्सी

पथ प्रवाह, जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़।

जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने सोमवार को पिथौरागढ़ में जनसुनवाई के दौरान एक सराहनीय पहल करते हुए जनपद के आठों विकासखंडों के हाईस्कूल टॉपर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को कुछ समय के लिए स्वयं जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया।

सम्मानित छात्र-छात्राएँ

सम्मान पाने वालों में– कमलेश कुमार (बेरीनाग), लोकेश नाथ गोस्वामी (बिण), कैलाश सिंह (धारचूला), हिमांशु भट्ट (डीडीहाट), रोहित सिंह (गंगोलीहाट), शिवांगी जोशी (कनालीछीना), कृतिका

खैनाल (मुनाकोट), गीतांजलि दानू (मुनस्यारी) शामिल रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना और भविष्य में नेतृत्व व जनसेवा के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है।

छात्रों के लिए जीवनभर की सीख

चयनित छात्रों ने इस अनुभव को जीवनभर की सीख बताते हुए आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसी पहल जारी रहेगी ताकि जनपद के अधिक से अधिक युवाओं को मार्गदर्शन और अवसर मिल सके।

जनता की समस्याओं पर फोकस

कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनीं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को हर सोमवार वर्चुअल माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा– जनता की समस्या मेरी समस्या है और इसके समाधान हेतु जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा।

उन्होंने ग्राम प्रधानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक ही टीम के सदस्य हैं और मिलकर ही जनता की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष नबियाल, उपजिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एक नजर

जनपद हरिद्वार में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे स्वास्थ्य शिविर

पथ प्रवाह हरिद्वार।

स्वास्थ्य नारी सशक्त अभियान कार्यक्रम के तहत जनपद हरिद्वार में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाएंगे। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरके सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य नारी ,सशक्त अभियान अगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित (पोषण माह) के साथ अभिशरण में रहेगा। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश में किया जाना प्रस्तावित है। अभियान के सफल संचालन के लिए 09 सितंबर की प्रातः 11 बजे विकास भवन सभागार में सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड शासन डॉ आर राजेश कुमार द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए संबंधित अधिकारियों को नियत स्थान एवं समय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है।

शराब तस्करों पर पिथौरागढ़ पुलिस का प्रहार लगातार जारी

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़ /08 सितम्बर। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ गोविन्द बल्लभ जोशी तथा क्षेत्राधिकारी धारचूला के.एस. रावत के पर्यवेक्षण में होटल/ढाबों की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचने एवं शांति व कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 08 सितम्बर 2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लिन्ठ्यूडा तिराहे के पास ढाबे की आड़ में शराब बेचने/पिलाने की सूचना पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ढाबा संचालक विक्रम सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी लिन्ठ्यूडा, पिथौरागढ़ को 11 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

भारत रत्न पं. गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर शुरू हुई टेबल-टेनिस प्रतियोगिता

60 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी, पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले

पथ प्रवाह, जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़।

भारत रत्न पं. गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर सोमवार को सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, टकाना (पिथौरागढ़) में जिला स्तरीय टेबल-टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन खेल निदेशालय उत्तराखंड के सौजन्य से एवं जिला प्रशासन पिथौरागढ़ के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट और पूर्व साई प्रशिक्षक ललित मोहन जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में जिले के 60 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में भाग ले रहे हैं।

पहले दिन के परिणाम

ओपन बालिका वर्ग सुमन परिहार ने रितु फर्स्वाण को 2-0 से और सिमरन ने प्रियंका को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

अंडर-17 बालिका वर्ग सिमरन लोहिया ने ललिता धपोला को 2-0 से, जबकि भावना धपोला ने आरती लोहिया को 2-0 से मात दी। अंडर-17 बालक वर्ग ग्रुप-ए में ऋषभ ने कमल को 2-0 से, तनमय ने साहिल को 2-1 से और अभिनव ने ऋषभ को 2-1 से हराया। ग्रुप-बी में करन ने अनिरुद्ध को 2-0 और आयुष ने दिव्यम को 2-0 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर-15 बालक वर्ग युवराज ने अभिनव विश्वकर्मा को 2-0 से, आशीष कुमार ने दिव्यांशु क्षेत्री को 2-0 से और देवाशीष पांडे ने देव पाल को 2-1 से हराया।

प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग के साथ-साथ ओपन बालक-बालिका वर्ग में भी मुकाबले खेले जाएंगे। निर्णायक की भूमिका में देवांग जोशी, धर्मेंद्र सिंह टोलिया और दीपक सिंह रहे।

खेल प्रेमियों की मौजूदगी

इस अवसर पर उपक्रीड़ाधिकारी प्रताप सिंह, कै. देवी चंद, राजेंद्र सिंह जेठी, जनार्दन सिंह वल्दिया, मनोज पुनेठा, प्रकाश जंग थापा, लीलावती जोशी, सुनीता मेहता सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

एस.पी.एस. रावत बने प्रदेश संगठन महामंत्री, मोहित सिंह बिष्ट को मिला प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

साई ग्रेस एकेडमी इंटरनैशनल स्कूल देहरादून में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड की बैठक सम्पन्न, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. किशोर पंत की अध्यक्षता में संगठन को मिली नई ऊर्जा ।

देहरादून। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड ने संगठनात्मक ढाँचे को और मजबूत बनाते हुए नई नियुक्तियों की घोषणा की है। राजधानी देहरादून स्थित साई ग्रेस एकेडमी इंटरनैशनल स्कूल में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से एस.पी.एस. रावत को प्रदेश संगठन महामंत्री तथा मोहित सिंह बिष्ट को प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया।

इस अहम बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. किशोर कुमार पंत ने की, जबकि संचालन कुमाऊँ मंडल अध्यक्ष रुद्राक्ष जोशी ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष समरजीत सिंह के प्रस्ताव पर दोनों पदों का निर्धारण किया गया और उपस्थित पदाधिकारियों ने

नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। नव नियुक्त संगठन महामंत्री एस.पी.एस. रावत लंबे समय से शिक्षा और संगठनात्मक कार्यों से जुड़े रहे हैं। उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे एसोसिएशन के फाउंडर प्रदेश महामंत्री आदरणीय सत्यप्रकाश भटनागर के साथ मिलकर जिलों और मंडलों के बीच संगठनात्मक तालमेल को सुदृढ़ करेंगे और संगठन की नीतियों को राज्यभर में प्रभावी ढंग से पहुँचाएंगे। वहीं, युवा शिक्षाविद् मोहित सिंह बिष्ट को प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया है, जो संगठन की नीतियों, गतिविधियों और विचारों को मीडिया एवं समाज के बीच सशक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे। बैठक में शिक्षा जगत से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। निजी विद्यालयों के शुल्क नियमन, नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पंत ने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य मात्र संगठनात्मक विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय केवल शिक्षा देने तक ही नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और भावी पीढ़ी को संस्कारित करने का भी कार्य कर रहे हैं।

बैठक के अंत में यह तय किया गया कि संगठन अब और अधिक सक्रियता से कार्य करेगा तथा जिलों, ब्लॉकों और गाँवों तक संगठन की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सक्रियता संगठन को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

गौरतलब है कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड लंबे समय से राज्य में निजी विद्यालयों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए कार्यरत है। संगठन ने शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। देहरादून में सम्पन्न यह बैठक केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि संगठन की नई ऊर्जा और दूरदर्शी दृष्टि का प्रतीक रही।

पिथौरागढ़-चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दिन से बंद, महंगाई ने बढ़ाई मुश्किलें

जनता परेशान, नेता बेफिक्र – जल्द होगा केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन

जीवन सिंह बोहरा, पथ प्रवाह, पिथौरागढ़।

पिथौरागढ़ व चम्पावत की लाइफ लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है। सड़क बाधित होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जबकि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हालात पर संजीदगी से ध्यान नहीं दे रहे। जानकारी के अनुसार, सड़क बहाल

करने के नाम पर अब तक 22 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारी वाहन न आने से जिले में रोजमर्रा का सामान महंगा हो गया है। शिमला मिर्च, जो पहले 30 रुपये किलो बिक रही थी, अब 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह राशन, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। लोगों का कहना है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री व अल्मोड़ा लोकसभा सांसद अजय टम्टा जब भी क्षेत्र में आते हैं तो केवल औपचारिकता निभाकर लौट जाते हैं। जनता को उम्मीद थी कि इस गंभीर समस्या पर वह ठोस पहल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

महंगाई और सड़क बंदी से त्रस्त लोग अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क बहाल नहीं की गई तो वे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का पुतला दहन करेंगे।

देशवासियों को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा करना होगा - पीयूष गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में हर वैश्विक चुनौती का सामना करने की ताकत है। इसके लिए देशवासियों को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा करना होगा। उन्होंने व्यवसायियों से अपील की कि वे 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता दें और आयात पर निर्भरता कम करें।

गोयल नई दिल्ली में आयोजित 56वें ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड्स कार्यक्रम के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कई देश निर्यात पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जिससे भारत की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सभी को कदम बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 1955 में 10 मिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और भविष्य में इसमें और तेजी की संभावना है। गोयल ने एमएसएमई सेक्टर को व्यापार और व्यवसाय की रीढ़ बताते हुए कहा कि देश का आत्मविश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

एक नजर

भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए - राष्ट्रपति

नई दिल्?ली (ईएमएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि प्राचीनकाल में भारत अध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था। भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने यहां आयोजित ईईपीसी इंडिया के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) इंडिया के सभी हितधारक देश में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके भारत को एक अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लें। राष्ट्रपति ने आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते ईईपीसी से आग्रह किया कि वह इस संकल्प को पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाए।

राष्ट्रपति ने खुशी जताई कि पिछले 10 वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 70 अरब डॉलर से बढ़कर 115 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चुनौतियों के बावजूद यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि में योगदान के लिए ईईपीसी की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ईईपीसी अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच सेतु का कार्य करता है। विश्व व्यापार व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचे में हो रहे बदलावों के बीच इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को भारत को अवसर में बदलना होगा। सात दशकों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात गंतव्य काफी बदले हैं और ईईपीसी को इस परिवर्तनशील प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग उत्पाद और सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध कराना भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज दुनिया की प्रमुख कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में हैं। ऐसे में हितधारकों को उपयुक्त प्रोत्साहन और पारिस्थितिकी तंत्र देकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इनोवेशन इकोनॉमी ही सबसे प्रतिस्पर्धी और समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और इसी राह पर भारत को अग्रसर करना सभी हितधारकों का कर्तव्य है।

भारत ने बनाया अंतरिक्ष टारगेटः 2040 तक चंद्र मिशन

मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले दशक में विज्ञान का हुआ लोकतंत्रीकरण

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने विज्ञान प्रशासकों के लिए एक सप्ताह के आवासीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/मॉड्यूल की घोषणा की है। यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) की एक पहल है, जिसका नेतृत्व आईएनएसए के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने ने आज यहां कर्तव्य भवन में मंत्री महोदय से मुलाकात की। डॉ.जितेंद्र सिंह ने इस अग्रणी पहल की सराहना की और निर्देश दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को सिविल सेवा प्रशिक्षण मॉड्यूल की तर्ज पर विशिष्ट बनाया जाए, जिससे भावी विज्ञान प्रशासकों को आगे के कार्यों के लिए अनुभव प्राप्त हो सके। नियम-आधारित से भूमिका-आधारित क्षमता निर्माण की ओर बदलाव पर जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि इस मॉड्यूल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (i-GOT) कर्मयोगी पोर्टल पर शामिल किया जाए।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालयः 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com